

3. यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या 674/XXVII(5)/2006, दिनांक 13 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(इन्दिरा आशीष)


सचिव।

संख्या : 45-दो(2)/XXXVI(1)/2006-85-दो(1)/03-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4. वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
5. एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


13/11/2006
(आलोक कुमार वर्मा)

अपर सचिव।

N.I.C

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उच्च न्यायालय,
उत्तरांचल, नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 13 नवम्बर, 2006

विषय: प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग(शेड्यूलि आयोग) की संस्तुतियों को उत्तरांचल राज्य द्वारा स्वीकार किये जाने के क्रम में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को वाहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम राष्ट्रीय वेतन आयोग(शेड्यूलि आयोग) द्वारा की गई संस्तुतियों को उत्तरांचल राज्य के शासनादेश संख्या 54-एक(1)/XXXVI(1)/2006-6-एक(2)/06, दिनांक 25.8.2006 द्वारा स्वीकार किये जाने के क्रम में उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1(1) में उल्लिखित ऐसे न्यायिक अधिकारियों को जिन्हें पूर्व में वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं थी और वर्तमान संस्तुति के क्रम में उन्हें वाहन उपलब्ध कराया जाना है के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत रुपये 40,00,000/- (रुपये चालीस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) ऐसे न्यायिक अधिकारियों को जिन्हें पूर्व में वाहन भत्ता स्वीकृत हो, उन्हें वाहन की स्वीकृति के उपरान्त वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।
- (2) शासकीय वाहन के क्रय हेतु अनुमन्य व्यापार कर में छूट हेतु फार्म डी निष्पादित कर क्रय की कार्यवाही की जाय ।
- (3) वाहन का क्रय डी०जी०एस० एण्ड डी० की दरों पर किया जाय ।
- (4) उक्त वाहन के क्रय में स्टैंडर्ड एक्सेसरीज के अलावा अन्य एक्सेसरीज हेतु धनराशि सम्मिलित नहीं है ।
- (5) न्यायिक अधिकारियों को आबंटित वाहनों की सूची भी शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामें डाला जायेगा ।